

सितम्बर में 29 तारीख वाले रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। हकलाना-काब्बा बोलना कोई झिझक की बात नहीं है। टुकड़ों में ही बातों के बारे में बेफिकर रहिये।

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 303

1/-

सितम्बर 2013

## मजदूर समाचार से संबंधित साधियों को एक पत्र

पिछला अंक पढ़ते हुये “जॉचवालों का आना” पर विशेष ध्यान गया। उत्पादन के कार्यस्थल का एक अनुपम चित्र उभारा गया है उसमें। कार्यस्थल की अनिश्चितता, आकस्मिकता, उसका बिखराव, उसकी अस्त-व्यस्तता बहुत बखूबी उभारे। उसमें घूमता-फिरता युवा साथी, जो वहाँ काम करता है, की घुमक्कड़ी से वहाँ की छिद्रित सज्जा, फिसलन, और उसका क्रम-रहित होना दिखा। ये तो कई कार्यस्थलों का विवरण हो सकता है।

कार्यस्थलों में बसी ये हड़बड़ी अकसर विवरण में आ ही नहीं पाती। पिछले दो सालों में आप अपनी पत्रिका में कार्यस्थल पर से मैनेजमेंट का कब्जा हटाने और कब्जा हटने पर दुनिया को देखने के बारे में काफी गहन चर्चा करते आये हैं। लेकिन एक बात जो पिछले अंक के कार्यस्थल के विवरण से तीखेपन से उभरती है, वो ये है कि ये “कब्जा” हमेशा ही डाँवाडोल होता है।

और शायद यही कारण है कि मैनेजमेंटों का अपने कार्यस्थलों के मजदूरों के प्रति आक्रामकता का जो रुख है, वो बढ़ता जा रहा है। तभी शायद मानेसर, गुड़गाँव, नोएडा की फैक्ट्रियों से 500-600 मजदूर आज की तारीख में काफी समय से जेल में हैं — बिना जमानत। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ही समय में इतने लोग कब्जे से टकराव के कारण जेल में हैं। ये एक बड़े चक्रवाती तूफान का चिन्ह है। ये हमारे बीच है, अभी है।

दूरबीन से देखो तो यही कार्यस्थल दो प्रमुख धाराओं में विभाजित हो जाते हैं। एक धारा, जो मजदूरों के हित और पक्ष में खुद को दिखाती है, वो दर्शाती है कि दरअसल मैनेजमेंट का कार्यस्थल पर पूरी तरह कब्जा है। इस धारा के मुताबिक, टाइम और लाइन का पूर्ण रूप से शासन है। जो रिसाव आप अपने चित्रण में उभार रहे थे, उसे ये धारा नजरअंदाज करती है। इसलिये यह धारा श्रमिक के थके हुये और बेचारा होने की छवि को बार-बार पुष्ट करती है।

दूसरी धारा इसी रिसाव को समाज का फेलियर, उसकी कमी, असफलता, हार, भूल मान कर श्रमिक पर आक्रमण करती है, कि कोई काम नहीं करता-करती। “कामचोर”, “नालायक”, “निकम्मा” जैसे शब्दों को अपना औजार बना कर धावा बोलती है। इस धारा की चुभती आवाज वैसे आजकल काफी हद तक मूर्खता लगती है।

एक तीसरी धारा भी है। वो ये सुर पकड़ती है कि अभी चीजें थोड़ा

उथल-पुथल हैं, लेकिन लोग अगर आज अपने संकल्प, मर्जी, इरादों, इच्छा-शक्ति का समर्पण करें, तो कल उनके लिये और सब के लिये बेहतर हो जायेगा। ये अलग बात है कि इस धारा के प्रेमियों का “कल” तेजी से दूर जाते हुये अदृश्य होता जा रहा है।

पर इस सब से हट कर तरेड़-दरार और रिसाव के फैलाव को सोचा जाये तो ये हैं जो एक उपजाऊ, सक्रिय, जीवन्त जीवन गति हैं।

**दरार-तरेड़, रिसाव** से शुरू करें तो इन्सान का एक अलग ही रूप उभर के आता है। मजदूर समाचार ने इस रूप को उभारने की जो चुनौती ली है, इससे जरूर हमारी तरह और भी पाठकों को उत्तेजना महसूस हुई होगी।

[ II ]

दरार-तरेड़ और रिसाव हर वक्त सत्ता के आत्म-विश्वास और क्षमता को प्रश्न-चिन्ह में रखती हैं। टूटने की कगार पर तो सत्ता हथियारबंद सिपाहियों को सामने ला खड़ा करती है। पूर्ण टूट में सिपाही, सिपाही ही नहीं रहते।

पर ये आत्म-विश्वास और क्षमता किस चीज के हैं ?

भविष्य को आँकने और उसे छवि देने का आत्म-विश्वास। और उसके महीन-बारीक फैलाव का अभ्यास करवाने की क्षमता। सत्ता क्षितिज को आँक पाने का दावा करती है। और साथ ही, जीवन का उल्लास, सम्बन्ध बनाने की चाहत, और दुनिया के विस्तार के प्रति जिज्ञासा पर अंकुश लगाती है। किसी और के क्षितिज देखने के उत्साह पर चोट मारती है। और, उसकी बौद्धिक रूप से उपेक्षा करने की पूरी कोशिश में रहती है।

एक साथी ने एक बार अपनी सोच में चल रही बहस को सब के बीच रखते हुये कहा था, “सवाल ये है कि क्षितिज के बारे में कौन सोचेगा ? बहस इसकी है।” क्षितिज कौन सोचेगी, कौन तय करेगी ? क्षितिजों का टकराव है, क्षितिजों पर मंथन है।

मजदूर समाचार और उसके पाठक मिल कर सत्ता के आत्म-विश्वास को काटते हुये, इसके क्षितिज भेदती हुई सोचों को जगह दे सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और उभार सकते हैं, तो ये आज का लम्हा दुनिया का एक अनमोल लम्हा बन सकता है।

कहा जाता है कि ब्रह्मांड ने मानव को जन्म दिया है ताकि अपने आप को समझ सके। शायद इस कथन को तीव्रता प्रदान का समय है ये। —

## 18 जुलाई पे एक बातचीत

बातचीत शायद चार घण्टे चली। कमरे में बैठे थे, बिजली नहीं थी, बहुत गर्मी थी। न उसको होश था, ना मुझे। बाकी सब तो बार-बार बाहर जा रहे थे, वापस आ रहे थे।

बातचीत में महसूस हुआ कि 18 जुलाई 2012 के बाद 18 जुलाई का वजन बढ़ता जा रहा है। लाखों मजदूरों की भाषा, हाव-भाव, और क्रियाओं में 18 जुलाई ने एक नई रंगत, नई जवानी, नई शक्ति ला दी है।

मैनेजमेंटों का रौब-दाबः — फैक्ट्री बन्द कर देंगे की धमकी; — अपमानजनक व्यवहार;

— बाउन्सरों व पुलिस को बुलाना;

— नौकरी से निकालने की धमकी और नौकरी से निकालना; — बड़ी संख्या में मजदूरों को दस्तावेजों में दिखाना नहीं; — मजदूरों की हलचलों में जो उभरें उन्हें तत्काल निकाल देना;

— तनखा और ओवर टाइम के पैसे खा जाना; मैनेजमेंटों के यह रौब-दाब पिछले एक वर्ष से आई.सी.यू. में भर्ती होते जा रहे हैं। रौब-दाब में रहें अथवा साँस लें में से चुनना अरजेन्ट आवश्यकता बनता जा रहा है।

ओय की बोली बोलना सुपरवाइजर-मैनेजर तेजी से भूल रहे हैं। मैनेजमेंट शब्दकोष पतले हो रहे हैं — अपमानजनक शब्द उन में से लुप्त हो

रहे हैं। परसनल गार्ड रखने के खर्च बढ़ रहे हैं। मनोरोगों के उपचार में समय और व्यय बोझ बन रहे हैं। नौकरी से निकालने में डर बढ़ रहा है। नौकरी से जिन्हें निकाल दिया था उन्हें वापस बुलाने के उपाय करने पड़ रहे हैं। दस्तावेजों में मजदूरों को बढती संख्या में दिखाने लगे हैं।

बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों के बीच गहरे और व्यापक सम्वाद तथा आदान-प्रदान तो थे ही, 18 जुलाई के बाद यह उभर कर सामने आ गये हैं। बातचीत में लगा कि मजदूरों में यह बातें बढ़ रही हैं कि कोई भी मजदूर हो ही क्यों।

बाद में ख्याल आया कि हमें बाहर ही बैठ कर बात कर लेनी चाहियें थी — गर्मी से बच जाते। बाहर पेड़ की छाँव और हवा थी। ■

# फैक्ट्रियों में हालात की एक झलक

★ 1.7.2013 से हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन : अकुशल मजदूर : 5342 रुपये (8 घण्टे के 205 रुपये) ; उच्च कुशल मजदूर : 5992 रुपये (8 घण्टे के 230 रुपये) । पोस्ट कार्ड डालने के लिये एक पता : श्रीमान श्रम आयुक्त, हरियाणा सरकार, 30 वेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ ।

★ दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (1.4.2013 से) अकुशल श्रमिक : 7722 रुपये (8 घण्टे के 297 रुपये) ; अर्ध-कुशल श्रमिक : 8528 रुपये (8 घण्टे के 328 रुपये) ; कुशल श्रमिक : 9386 रुपये (8 घण्टे के 361 रुपये) स्नातक और अधिक (स्टाफ) : 10,218 रुपये (8 घण्टे के 393 रुपये) । पोस्ट कार्ड डालने के लिये एक पता : श्रम आयुक्त दिल्ली सरकार, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054

**एस्कोर्ट्स मजदूर :** “फरीदाबाद स्थित समूह की सब फैक्ट्रियों में अब 3000-3500 स्थाई मजदूर ही बचे हैं। मैनेजमेन्ट के साथ तीन वर्षीय समझौता यूनियन लीडरों ने 3 अगस्त को सुनाया। स्थाई मजदूरों के 3 साल में 8500 रुपये बढ़ेंगे जबकि 12-13 हजार की बातें थी। अब स्थाई मजदूर की तनखा 32,000 रुपये से ज्यादा हो गई। थर्ड प्लान्ट में अब स्थाई मजदूर 410 ही हैं। मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौते में मैनेपावर कम की है। मैनेजमेन्ट ने मोस्ट कम्पनी से अध्ययन करवाया था। थर्ड प्लान्ट में एक शिफ्ट में 110 ट्रेक्टर बनते थे, 4 मिनट 5 सैकेण्ड में एक ट्रेक्टर। समझौते के बाद 1 अगस्त से यहाँ ट्रेक्टर असेम्बली में दूसरी शिफ्ट भी आरम्भ कर दी है और प्रतिदिन 150 ट्रेक्टर बनना निर्धारित किया है। पहली शिफ्ट में निर्धारित 110 की जगह 90-95 ही बनते हैं। ऐसे में दूसरी शिफ्ट वालों को निर्धारित 40 से ज्यादा बना कर 150 ट्रेक्टर पूरे करने पड़ते हैं। दूसरी शिफ्ट में स्थाई मजदूर बहुत कम और अस्थायी मजदूर ज्यादा हैं। थर्ड प्लान्ट की मेन असेम्बली लाइन पर बिफोर पेन्ट में पहले जहाँ 56 लगते थे वहाँ अब 47 लग रहे हैं और मोस्ट की सलाह 39 रखने की है। पेन्ट लाइन पर एक-दो स्थाई मजदूर और बाकी सब ठेकेदारों के जरिये रखे हैं। आफ्टर पेन्ट लाइन पर पहले 101 थे अब 75 हैं, 50 स्थाई और 25 अस्थायी। थर्ड प्लान्ट में स्थाई और अस्थायी मजदूर बराबर हो गये थे पर इधर दूसरी शिफ्ट शुरू होने के बाद नये अस्थायी मजदूर भर्ती किये हैं। अब कम्पनी कैजुअल वरकर भर्ती करने की बजाय ठेकेदारों के जरिये मजदूर रखने लगी है और ठेकेदार बहुत हो गये हैं। पहली शिफ्ट के अस्थायी मजदूरों को दूसरी शिफ्ट में भी रोक लेते हैं और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। स्थाई मजदूरों में इम्पलाई सन्स 5-600 हैं और उन्हें एल टी ए तथा मेडिकल के पैसे पुरानों से आधे देते थे पर समझौते में अब बराबर कर दिया है। लेकिन डी ए के 4500 रुपये बेसिक में डाल दिये हैं जिसका मतलब है स्थाई मजदूर लगने पर तनखा जो 11,650 रुपये थी वह अब आगे से 7800 रुपये होगी। ब्रेक डाउन, मैटेरियल शॉर्टेज, स्पलाई लाइनों में कमी के कारण अगर बीच में लाइन बन्द करनी पड़ती है तो फिर उत्पादन के फेर में लाइन की रफ्तार बढ़ा देते हैं जिससे मजदूरों को बहुत परेशानी होती है। और, 31 जुलाई तक सुबह 8 बज कर 5 मिनट तक अन्दर जा सकते थे लेकिन अब 8 से एक सैकेण्ड भी लेट होने पर आधे घण्टे के पैसे काटेंगे, यानी, सड़क पर मजदूर के मरने की सम्भावना बढ़ेगी।” और, 16 अगस्त को फर्स्ट प्लान्ट के गेट पर ठेकेदार के जरिये रखा एक मजदूर : “हमारी बातें नहीं लिखते। हमें जुलाई की तनखा आज 16 अगस्त तक नहीं दी है।”

**ए ए ऑटोमैक श्रमिक :** “प्लॉट 157-58 सैक्टर-5, आई.एम.टी. मानेसर स्थित फैक्ट्री में मात्र एक स्थाई मजदूर, 700 कैजुअल वरकर और तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 500 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में होण्डा, हीरो, सुजुकी दुपहियों के हिस्से-पुर्जे तथा अमरीका निर्यात के लिये हैडर फिल्टर बनाते हैं। रविवार को, त्यौहार को, 15 अगस्त को भी ड्युटी — 15 अगस्त को बाहर ताला लगा कर काम करवाया, मोबाइल गेट पर रख लिये, नाम लिख कर बोरी में रखे, स्टाफ के भी रखे, एक बोरी से ज्यादा मोबाइल हो गये। शिफ्ट रविवार को बदलती है तब कुछ मजदूरों की 24 घण्टे ड्युटी हो जाती है। भट्ठी और प्रेशर डाई कास्टिंग वालों को जबरन 24-36-48 घण्टे रोक लेते हैं — गेट पर फोन कर निकलने नहीं देना कह देते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। ठेकेदारों के जरिये रखे 500 मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। अब 23 अगस्त को 700 कैजुअल वरकरों की ई.एस.आई. कार्ड के लिये फैक्ट्री में ही फोटो खींची हैं, पाँच-सात के ही परिवार फोटो के लिये आये, बाकी की अकेले की फोटो। पे-स्लिप नहीं देते। पी.एफ. नम्बर नहीं बताया। मात्र एक गेट नम्बर देते हैं। तनखा से काटे ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे जमा करते हैं

सितम्बर 2013

कि नहीं का पता नहीं चलता। डेढ वर्ष बाद एक कैजुअल वरकर ने नौकरी छोड़ी, उसका 12 महीने का ही पी.एफ. जमा था। निर्यात वाले हैडर फिल्टर के लिये बहुत मारामारी है। पाँच मशीन हैं, हर मशीन से एक शिफ्ट में 350 चाहियें। अगर दो पीस भी कम बने तो क्यों कम बने। पानी-पेशाब में भी दिक्कत। रात 2 बजे, 3 बजे भी मैनेजर घर से सुपरवाइजर को फोन करता रहता है। कैन्टीन में रोटी कच्ची, सब्जी कच्ची-पक्की, दाल में स्वाद नहीं और चाय तो गंगाजी का जल — न चायपत्ती का पता चलता, न दूध का पता चलता।”

**फोरमोस्ट कामगार :** “70-71 उद्योग विहार फेज-1, गुडगाँव स्थित फैक्ट्री में 900 मजदूर पुरुषों की कमीज बनाते हैं। चार सौ महिला मजदूरों की सुबह 9½ से रात 9 की ड्युटी है। पुरुष मजदूरों को रोज रात 1 बजे तक काम करना पड़ता है, रविवार को रात 9 बजे छोड़ देते हैं। फैक्ट्री में 15 अगस्त को भी सब मजदूरों की रात 8 बजे तक ड्युटी थी। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। एक भी स्थाई मजदूर नहीं है। सब अस्थायी मजदूर हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. 900 मजदूरों में एक की भी नहीं हैं। तनखा हर महीने देरी से, जुलाई की 22 अगस्त को दी।”

**फुड एण्ड बायोटेक इंजीनियर्स वरकर :** “छपरौला रोड़, पृथला, पलवल स्थित फैक्ट्री में 250 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में दूध के तथा रसायनों के कन्टेनर बनाते हैं। रविवार को दिन में 8 घण्टे काम। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. परमानेन्ट कहे जाते 100 मजदूरों के ही हैं और इनकी तनखा 3000-3500-4000-10,000 रुपये। आठ ठेकेदारों के जरिये रखे 150 मजदूरों में 25 लड़के 16-17 वर्ष के हैं। श्रम विभाग, ई.एस.आई., पी.एफ. वाले जाँच के लिये आते हैं तब 150 मजदूरों को साइड में कर देते हैं। जाँच वाले कुछ को पकड़ लेते हैं तो 20-25 हजार रुपये दे कर रफा-दफा करते हैं। बोनस किसी मजदूर को नहीं देते जबकि रजिस्ट्रारों में दिया दिखाते हैं। फैक्ट्री 2010 में फरीदाबाद से पृथला शिफ्ट की तब कहा था कि तनखा बढ़ायेंगे, आने-जाने के लिये वैन लगायेंगे। एक महीने बाद मजदूरों ने पूछा तो मना कर दिया : करना है तो करो वर्ना जाओ। कम्पनी के फरीदाबाद में गुरुकुल, सराय तथा सैक्टर-58, रुड़की में, बिहार में वैशाली में प्लान्ट हैं। माल पृथला फैक्ट्री से निकलता है और कागजों में कभी रुड़की, कभी फरीदाबाद में सैक्टर-58 से दिखाते हैं। पिछले वर्ष एक्साइज वालों ने छापे में फर्जी बिल पकड़ कर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।”

**रीको ऑटो इन्डस्ट्रीज मजदूर :** “38 किलोमीटर, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुडगाँव स्थित फैक्ट्री में जनरल मोटर, फोर्ड, मारुति सुजुकी, वोल्वो, टोयोटा, टाटा, रेनॉ कारों तथा होण्डा व हीरो दुपहियों के लोहे और अल्युमिनियम के हिस्से-पुर्जे बनते थे। सबसे बड़े दो बायर, जनरल मोटर और फोर्ड को 2009 में हड़ताल के समय कम्पनी माल नहीं भेज पाई इसलिये उन्होंने 2010, 2011 से रीको से माल लेना बन्द कर दिया। बी एम डब्लू नया बायर बना है। जनरल मोटर तथा फोर्ड के 15-20 कम्पोनेन्ट बनाते ठेकेदारों के जरिये रखे सब मजदूर निकाल दिये और स्थाई मजदूरों में से कुछ को अन्य कार्यस्थल पर भेजा लेकिन मशीन शॉप के 200 को खाली बैठाया। तीन-चार महीने खाली बैठा कर 2-2, 4-4 कर 2011 में सब को निकाल दिया। जो मजदूर चुप रहे उन्हें हिसाब में 2 लाख और जिन्होंने विरोध किया उन्हें 3½ लाख रुपये दिये। यूनियन है, साल में स्थाई मजदूर से 120 रुपया चन्दा लेती है, मैनेजमेन्ट की यूनियन है। डेढ-दो वर्ष में 4000 मजदूरों को 2500 कर दिया, जिनमें 1000 ही स्थाई हैं। और फिर, फैक्ट्री को शिफ्ट करना आरम्भ कर दिया है। हफ्ता-दस दिन में 2-2, 3-3 मशीनें ले जा रहे हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को निकाल रहे हैं और परमानेन्ट को उनकी जगह लगा रहे हैं। कम्पनी (बाकी पेज तीन पर)

फरीदाबाद मजदूर समाचार

की 3 फैक्ट्रियाँ आई.एम.टी. मानेसर में हैं, एक भिवाड़ी में और डाई कास्टिंग की नई फैक्ट्री बावल में बनाई है। आशंका है कि 14 से 25,000 रुपये तनखा वाले स्थाई मजदूरों को नहीं ले जायेंगे। चर्चा है कि चार-पाँच वर्ष में हीरो होण्डा चौक से टोल टैक्स तक की सब फैक्ट्रियाँ उठेंगी..... सोना स्टीयरिंग आधी चली गई है।”

**लखानी वरदान श्रमिक :** “प्लॉट 144 सैक्टर-24, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री से मजदूर (करीब 100) प्लॉट 265 भेज दिये गये थे। बैंक ने प्लॉट 144 पर ताला लगाया। तब समूह का चेयरमैन और उसका डायरेक्टर बेटा प्लॉट 265 में आये और मजदूरों से कहा कि मदद करो, प्लॉट 144 का ताला तोड़ कर अन्दर जाओ। मजदूरों ने इनकार कर दिया। एक बार तनखा में देरी का विरोध करते मजदूरों पर कम्पनी ने पुलिस से लाठियाँ चलवाई थी। दूसरी बार कम बोनस का विरोध करते मजदूरों पर कम्पनी ने पुलिस गाड़ियों से पानी की बौछार और लाठियाँ चलवाई। नौकरी छोड़ चुके मजदूरों को दो वर्ष बाद भी कम्पनी ने हिसाब नहीं दिया है। इधर जून की तनखा 1 अगस्त को दी। कम्पनी और बैंक के झगड़े में मजदूर लाठियाँ क्यों खायें? और फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर क्यों काटें? तब 144 से 265 भेजे मजदूरों से साहबों ने प्लॉट 144 जाने को कहा। मजदूर वहाँ गये — ताला लगा था और बैंक के गार्ड थे। मजदूर बाहर रहे और शिफ्ट समाप्ति पर अपने निवासों को चले गये। रात को डायरेक्टर बेटा 100 लोगों को ले कर फैक्ट्री पहुँचा, बैंक गार्डों को धकेल कर ताला तोड़ फैक्ट्री में प्रवेश किया। उन 100 में फैक्ट्री का कोई मजदूर नहीं था पर प्रचारित यह किया कि मजदूर ताला तोड़ कर अन्दर गये हैं और काम कर रहे हैं। सुबह मजदूर ड्युटी के लिये पहुँचे तो फैक्ट्री खुली मिली और उन्होंने प्रवेश किया। काम वहाँ पहले से ही बन्द था तभी तो उन्हें प्लॉट 265 भेजा गया था। मजदूर खाली बैठे। पुलिस-प्रशासन-लखानी वरदान मैनेजमेन्ट-बैंक अधिकारियों की इस नौटंकी में मैनेजमेन्ट ने प्लॉट 144 से महेगी मशीनें हटा ली हैं। आज 14 अगस्त तक भी मजदूर अन्दर जा कर खाली बैठ रहे हैं। इस बीच साहबों ने एक सुपरवाइजर और 19 सफाई कर्मचारियों को ताला तोड़ कर फैक्ट्री में प्रवेश करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार किया है। प्रत्येक को इसके लिये 30-40 हजार रुपये देने की चर्चा है। पुलिस ने उन सब को गिरफ्तार किया। जमानत पर छूट गये हैं।”

**होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर कामगार :** “प्लॉट 1 व 2 सैक्टर-3, आई.एम.टी. मानेसर स्थित फैक्ट्री में अब प्रतिदिन 3300 स्कूटर और 2300 बाइक बनती हैं। बाइक इन्जन असेम्बली को उदाहरण लें तो एक शिफ्ट में 3 इंजीनियर, 1 सुपरवाइजर, 12 स्थाई मजदूर और ठेकेदारों के जरिये रखे 100 मजदूर काम करते हैं। स्थाई मजदूर रिलीवर हैं, छोटा व हल्का काम करते हैं। लाइन 2 पर 16-17 सैकेण्ड में एक इंजन तैयार होता है। इस समय प्रोडक्शन में तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 8-9 हजार मजदूर काम करते हैं। दिसम्बर 2012 में मैनेजमेन्ट-यूनियन तीन वर्ष के समझौते में स्थाई मजदूरों की तनखा 15 हजार रुपये बढ़ाई है जबकि ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की 2250 रुपये — 500 बेसिक में, 500 एच आर ए के, 1250 रुपये प्रोडक्शन के। एक वर्ष काम करने के बाद ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूर परीक्षा में बैठ सकते हैं। नवम्बर 2012 में हुई परीक्षा में 5000 बैठे थे। रिजल्ट मई-जून में आया, 171 पास किये हैं। अगस्त-मध्य में इन 171 का इन्टरव्यू हुआ है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। इन्क्वायरी होगी यहाँ से घर तक की। फिर मात्र 50 को कम्पनी कैजुअल बनाया जायेगा। दो साल कम्पनी कैजुअल रखने के बाद फिर 2 वर्ष ट्रेनी रखेंगे। फिर परमानेन्ट।”

**नोर ब्रेम्से वरकर :** “14 /6 मथुरा रोड, फरीदाबाद से डेढ महीने पहले फैक्ट्री पलवल के बघौला गाँव चली गई है। दो ठेकेदारों के जरिये रखे 500 मजदूर और 38 स्थाई मजदूर रेलवे के एयरब्रेक, शॉकर, एयर ड्रायर आदि बनाते हैं। जर्मनी में मुख्यालय वाली कम्पनी में 10 वर्ष से काम कर रहे मजदूर भी अस्थाई हैं। फरीदाबाद में दो शिफ्ट थी, बघौला में अभी एक शिफ्ट ही है। तनखा बढ़वाने और बस लगवाने के लिये शुक्रवार, 9 अगस्त को ठेकेदारों के जरिये रखे 500 मजदूरों ने काम बन्द किया, भोजन नहीं किया, चाय नहीं पी। दोपहर बाद 3-4 बजे मैनेजमेन्ट ने दिलासा दी, माँग पूरी कर देंगे, भोजन करो और फिर खाना खिलाने बघौला ले गये।

अगले दिन ड्युटी के लिये पहुँचे तो गेट पर 20-25 बाउन्सर थे, बन्दूक भी दिखा रहे थे। स्थाई मजदूर अन्दर गये और ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को बाहर रोक लिया। धमकाया। समझौता कर लो। दो घण्टे बाद 4 अन्दर गये, कम्पनी ने बस अथवा 1000 रुपये में से एक चुनने को कहा। बस शुरू हो गई हैं। दो-तीन बदमाश फैक्ट्री के अन्दर चक्कर काटते हैं। यूनियन लीडरों को कहा— 38 स्थाई मजदूरों की यूनियन है — लीडरों ने मैनेजमेन्ट से पूछा : क्यों गुण्डे बुला रहे हो ?”

## दो स्थितियाँ

11 अगस्त को फरीदाबाद स्थित **ओसवाल इलेक्ट्रीकल** (48-49 इन्डस्ट्रीयल एरिया), **महावीर डाईकास्टिंग** (153-165 सैक्टर-24), **ओसवाल कास्टिंग** (21-22-23 सैक्टर-25) फैक्ट्रियों के तीन मजदूरों ने मिल कर बातें की :

तीनों फैक्ट्रियों में 12-12 घण्टे की ड्युटी, ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से, मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये रखा है, दस वर्ष से काम कर रहों को भी वर्दी-जूते नहीं, ई.एस.आई. व पी.एफ. कई के नहीं और जिनके हैं उन्हें भी छोड़ने पर फण्ड के पैसों के लिये बहुत परेशान होना पड़ता है, कई मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं देते, मँहगाई भत्ता आता है उसे 5-6 महीने खींच जाते हैं और एरियर खा जाते हैं, कैन्टीन नहीं, तीन-चार वर्ष से ठेकेदार बोनस के पैसे नहीं दे रहे और कहते हैं कि बिल पास होगा तब बाद में देंगे लेकिन उनका बाद कभी होता ही नहीं, श्रम विभाग वाले आते हैं और पैसे ले कर चले जाते हैं, तीन महीने से साप्ताहिक अवकाश 15 दिन बाद देते हैं और वह भी रविवार को नहीं देते जिससे मजदूरों के अन्य कार्यक्रम गड़बड़ा जाते हैं। यह बातें कहने पर मजदूर को निकाल देते हैं, अभी ही बैजू को निकाला है। अल्युमिनियम की डाईकास्टिंग का काम है और **टी.वी.एस.** व **हीरो** दुपहियों तथा **मारुति सुजुकी** कारों के हिस्से-पुर्जे बनते हैं।

और सितम्बर के आरम्भ में ओसवाल इलेक्ट्रीकल मजदूर :

20-25 दिन से काम मन्दा है। ओवर टाइम बन्द। आठ घण्टे की ड्युटी। सप्ताह में दो दिन फैक्ट्री बन्द। मैनेजर-सुपरवाइजर असभ्यता से पेश आने लगे हैं। महीने में 8 छुट्टी और ओवर टाइम बन्द की स्थिति में गुजारा कैसे होगा कहने पर कहते हैं कि जहाँ जाना है जाओ।

## नपिनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ... (पेज चार का शेष)

अभी विवाद चल रहा है कह कर यूनियन ने एक रविवार को 21 फरवरी के बदले काम करवाया। श्रम विभाग में मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच बातचीत शुरू। आठ-दस दिन बाद बात पर बात लेकिन बात बनी नहीं है। यूनियन ने 26 अगस्त से काली पट्टी शुरू करवाई। कोई असर नहीं। श्रम विभाग में 29 तारीख की बातचीत भी पहले जैसी। यूनियन ने 30 अगस्त को कम्पनी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

“मार्च 2012 से 800 मजदूरों में से 631 हर महीने यूनियन को 100-100 रुपये दे रहे हैं। पहले-पहल मजदूर को हर महीने 100 रुपये की यूनियन रसीद देते थे पर फिर यूनियन संघर्ष कोष की पर्ची देने लगे। तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 325 मजदूर हर महीने 100-100 रुपये देते हैं पर इन्हें यूनियन सदस्य नहीं बनाया है। यूनियन के सदस्य 306 स्थाई मजदूर ही हैं और वे ही यूनियन नेतृत्व में हैं। फैक्ट्री लीडर कहते हैं कि पैसे सब के बराबर बढ़ेंगे, सब स्थाई होंगे, पोजीटिव बातचीत चल रही है। पर कर्ता-धर्ता होण्डा का लीडर है और यहाँ सब मजदूर होण्डा फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों तथा ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की असलियत को जानते हैं। होण्डा फैक्ट्री में यूनियन जो कर रही है उसे हम जानते हैं। यहाँ कम्पनी कुछ स्थाई मजदूरों से और खासकर ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों से डरती है। माँग-पत्र में तीन वर्ष में 25,000 रुपये बढ़ाने की बात है पर सुना है कि कम्पनी 8,200 रुपये मानी है। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूर जानते हैं कि हमारा नीचे होगा, पर ज्यादा नीचे हुआ, 7000 रुपये से कम हुआ तो लीडरों को कह दिया है कि तुम अपनी यूनियन ले कर घूमना और कम्पनी को तो भुगतना ही पड़ेगा।”

महीने में एक बार छापते हैं, 10,000 प्रतियाँ निशुल्क बाँटने का प्रयास करते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें। अन्यथा भी, चर्चाओं के लिए समय निकालें।

जुड़ने-जोड़ने के लिये  
मजदूर हितैषी मजदूर

लक्ष्य है : मजदूरों की सक्रियता बढ़ाने में  
योगदान देना

सदस्य बनें, सहयोगी बनें

1. कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की ।
2. कानून अनुसार शोषण मुख्य तरीका है शोषण का । ..... भाप-कोयले की मशीनों के दबदबे के दौरान शोषण की दर एक सौ-दो सौ प्रतिशत थी । आज इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मशीनों के दौर में मजदूर आठ-दस मिनट के काम द्वारा अपनी दिहाड़ी पैदा कर देते हैं । आज शोषण की दर तीन हजार-चार हजार प्रतिशत है । ..... आज मजदूर जो पैदा करते हैं उसके आधे से ज्यादा हिस्से, पचास प्रतिशत से अधिक को सरकारें टैक्सों के रूप में वसूल करती हैं । आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक-डेढ़ प्रतिशत हिस्सा ही मजदूरों को मिलता है । यह मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा का मुख्य कारण है और इसकी समाप्ति के लिये मजदूरी-प्रथा का उन्मूलन एक अनिवार्य आवश्यकता है ।
3. .... हम बहुत बड़े परिवर्तन के दौर में हैं । ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की सक्रियता बहुत-ही जरूरी है अन्यथा बर्बादी हमारे सामने मुँह बाये खड़ी है । 4. इन हालात में कानून से परे शोषण के खिलाफ एक और संगठित प्रयास के तौर पर... **मजदूर हितैषी मजदूर** संगठन का गठन कर रहे हैं ।...
8. **मजदूर हितैषी मजदूर** संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हम सदस्य बनने की अपील कर रहे हैं । जो मजदूर दिन काटने की बजाय जीवन जीने के प्रयास करना चाहते हैं उन्हें हमारा निमन्त्रण है : **मजदूर हितैषी मजदूर** संगठन के सदस्य बनें । “समय नहीं है” के इस दौर में कुछ समय देना सदस्यता की अनिवार्य शर्त है । संगठन किसी भी संस्था से कोई आर्थिक योगदान नहीं लेगा इसलिये संगठन का सदस्यता शुल्क पाँच रुपये होगा और मासिक आर्थिक योगदान स्वैच्छिक ।
9. सदस्यों की संख्या और सक्रियता आगे चल कर संगठन की गतिविधियाँ निर्धारित करेगी । इस बीच तीन संयोजक और मित्र अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक मजदूर और मजदूर समूह को कानून से परे शोषण के खिलाफ कदम उठाने में सहयोग करेंगे ।
- मजदूर हितैषी मजदूर** संगठन का अस्थाई कार्यालय मजदूर लाइब्रेरी, ऑटोपिन झुग्गी, एन आई टी फरीदाबाद— 121001 है ।
- फोन : 0129—6567014
1. प्रताप सिंह, संयोजक : हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी रहे हैं और अब वकालत करते हैं, मुख्यतः कर्मचारियों के केस लड़ते हैं ।
- फोन : 9818772710
2. जवाहर लाल, संयोजक : पोरिट्स एण्ड स्पैन्सर (वॉथ) फैक्ट्री के मजदूर रहे हैं और अब श्रम न्यायालय में मजदूरों के केस लड़ते हैं । फोन : 9810933587
3. सतीश कुमार, संयोजक : गुडईयर टायर फैक्ट्री के मजदूर रहे हैं और अब “मजदूर मोर्चा” के सम्पादक हैं ।

फैक्ट्री रिपोर्ट  
नपिनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स

**नपिनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मजदूर :** “प्लॉट 7 सैक्टर-3, आई.एम.टी. मानेसर स्थित फैक्ट्री में सुबह 6 से 2½, दोपहर 2½ से 11, रात 11 से अगली सुबह 6 की शिफ्टों में 800 मजदूर **हीरो** दुपहियों तथा **मारुति सुजुकी** वाहनों के मेन वायर हारनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन में हीरो के तथा निर्यात के लिये पार्ट्स बनाते हैं ।

“मई-जून 2010 की बात है । एक दिन ए-शिफ्ट में काम में थोड़ी गलती पर एक मजदूर को धूप में खड़ा कर, कान पकड़वा कर ऊठक-बैठक लगवाने लगे । भूतल पर मेन वायर हारनेस के सब मजदूरों ने काम बन्द कर दिया और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन गये, वहाँ भी मजदूरों ने काम बन्द कर दिया । सब मजदूर काम बन्द कर बैठ गये । भोजन करने से इनकार किया । मजदूरों ने चाय भी नहीं पी । कम्पनी ने कैंटीन बन्द कर दी । ढाई बजे शिफ्ट समाप्त होने पर ए-शिफ्ट के मजदूर फैक्ट्री से नहीं निकले । बी-शिफ्ट के मजदूरों को प्रवेश करने से रोका गया तब तक आधे अन्दर पहुँच चुके थे । चार दिन मजदूर फैक्ट्री के अन्दर ही रहे । एक सौ महिला मजदूर ए-शिफ्ट में हैं और वे पुरुष मजदूरों के साथ थी । महिला मजदूर रात को फैक्ट्री में नहीं रुकती थी और बाहर लोग जो भोजन बनाते उसे सुबह ले कर फैक्ट्री में पहुँचती । आपस में बाँट कर मजदूर इक्ठे भोजन करते । चार दिन बाद श्रम विभाग से कोई आया और मजदूरों से पाँच प्रतिनिधि माँगे । कम्पनी चेयरमैन ने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे । तनखा कम है कह कर बढ़ाने को कहा तब चेयरमैन बोला कि फैक्ट्री बन्द कर दो, पैसा एक नहीं बढ़ायेंगे । मजदूर अड़े रहे तब तीन वर्ष में 3500 रुपये बढ़ाने का समझौता हुआ जिसमें उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाना था । तब निर्धारित उत्पादन अभी तक नहीं दिया है ।

“कम्पनी ने तैयारी की । मैनेजमेन्ट ने छॉट कर कुछ मजदूरों के 500-500 रुपये बढ़ाये । परमानेन्ट करने का लालच दिया । बाहर 400 को तैयार किया । पुलिस से सैटिंग की । फिर बहला-फुसला रखे 100 के जरिये भड़का कर मई 2011 में ए-शिफ्ट में हड़ताल करवाई । पुलिस आई और डण्डे मार कर मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर किया । बी-शिफ्ट को मैनेजमेन्ट ने अन्दर जाने ही नहीं दिया । फोन कर तैयार कर रखे 400 को अन्दर बुलाया, नई भर्ती की । बाहर की हड़ताल आठ-नौ दिन चली । स्थाई तथा अस्थाई मजदूरों में जो 150 लोग उभरे थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया । अधिकतर स्थाई मजदूर भी 20-25 हजार रुपये ही हिसाब में ले कर चले गये । नई भर्ती वाले 400 में से ज्यादातर को तब कम्पनी ने निकाल दिया ।

“इस बीच मारुति सुजुकी मानेसर मजदूरों ने जून 2011 में 13 दिन फैक्ट्री में कम्पनी की बोलती बन्द कर दी । नपिनो से निकाले गये स्थाई मजदूरों में से 12 ने हिसाब नहीं लिया था और श्रम विभाग पहुँचे थे । वहाँ चक्कर काटने के दौरान उनकी मुलाकात एक यूनियन लीडर से हुई जिसने उन्हें यूनियन का पंजीकरण करवाने के लिये कदम उठाने को कहा । चुपके-चुपके अन्दरवालों की मीटिंग हुई । नब्बे प्रतिशत राजी हो गये तब बाहर वाले 12 ने यूनियन पंजीकरण के लिये चण्डीगढ में फाइल लगाई । यह बन्दे तो टरमिनेट हैं कह कर मैनेजमेन्ट ने पंजीकरण फाइल बन्द करवा दी ।

“सितम्बर-अक्टूबर 2011 में मारुति सुजुकी मानेसर फैक्ट्री में मजदूरों की हलचलें बहुत बढ़ी तब तीन-चार बार नपिनो ऑटो के चार-चार सौ स्त्री व पुरुष मजदूर मारुति फैक्ट्री गेट पर गये । मार्च 2012 में फैक्ट्री में कार्यरत 12 पुराने स्थाई मजदूरों के जरिये नये सिर से यूनियन पंजीकरण के लिये फाइल लगवाई । मई में नब्बे प्रतिशत मजदूरों ने काली पट्टी लगाई 2011 से बाहर कर रखे 12 को वापस लेने के लिये । ओवर टाइम करना बन्द कर दिया — महीने में 150 घण्टे तक ओवर टाइम होता था जिसका भुगतान दुगुनी दर की बजाय सिंगल रेट से था । और फिर 18 जुलाई को तो मारुति सुजुकी फैक्ट्री में कमाल हो गया । बहुत मैनेजरों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और फैक्ट्री बन्द । नपिनो ऑटो मैनेजमेन्ट बहुत डर गई । साल-भर से बाहर 11 मजदूरों को अन्दर ले लिया । बचे एक को भी प्रोडक्शन में 50 पीस बढ़ाने पर वापस ले लिया । मई 2011 में टरमिनेट करने पर हिसाब नहीं लेने वाले 12 मजदूर अगस्त 2012 से वापस फैक्ट्री में हैं ।

“कम्पनी ने नपिनो में ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों के तौर पर बरसों काम करके छोड़ गये 50-60 मजदूरों को फोन करके वापस बुलाया और उन्हें एक वर्ष के लिये ट्रेनी रखा है । ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों में से 15 को 3 वर्ष के लिये ट्रेनी रखा है । अक्टूबर में यूनियन का पंजीकरण हो गया । यूनियन ने कम्पनी को माँग-पत्र दिया । दो-तीन महीने उस पर मैनेजमेन्ट ने बात नहीं की । नवम्बर में कम्पनी ने ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों में से चुन कर 51 को परमानेन्ट किया । जुलाई 2012 के बाद मैनेजमेन्ट ने मजदूरों को धमकाना बन्द कर दिया है ।

“ 20-21 फरवरी 2013 को पूरे भारत में हड़ताल के सिलसिले में 6 फरवरी को फरीदाबाद में श्रम मन्त्री को ज्ञापन देने गई यूनियनों के संग नपिनो ऑटो के 500 मजदूर भी थे । लेकिन 20 फरवरी को फैक्ट्री चली । नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों के उभार से कम्पनी डर गई और 21 फरवरी की छुट्टी की तथा बदले में रविवार को काम करने को कहा । मजदूरों ने मना कर दिया ।

(बाकी पेज तीन पर)